एन ईवनिंग इन पेरिस-डील, डीलर और पीएम मोदी

रवीश कुमार

एफल टावर के नीचे बहती सीन नदी की हवा बनारस वाले गंगा पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेरिस की शाम का हिसाब मांगने आ गई हैं। 10 अप्रैल 2015 की पेरिस यात्रा सिरे से संदिग्ध हो गई है। गंगा के सामने सीन बहुत छोटी नदी है लेकिन वो गंगा से बेहतर बहती है। उसके किनारे खड़ा एफ़लि टावर बनारस के पुल की तरह यूं ही हवा के झोंके से गिर नहीं जाता है। प्रधानमंत्री कब तक गंगा पुत्र भीष्म की तरह चुप्पी साधे रहेंगे। क्या अंबानी के लिए खुद को इस महाभारत में भीष्म बना देंगे ? न कहा जा रहा है न बचा जा रहा है।

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसुआं ओलान्द के बयान के बाद कि अंबानी का नाम भारत सरकार की तरफ से आया था, रफाएल विवाद में संदेह की सूई निर्णायक रूप से नरेंद्र मोदी की तरफ़ मुड़ गई है। 10 अप्रैल 2015 को नरेंद्र मोदी और ओलान्द के बीच ही रफाएल करार हुआ था। ओलान्द ने फ्रांस के प्रतिष्ठित अख़बार मीडियापार्ट से कहा है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अंबानी का नाम भारत सरकार की तरफ से आया था।

अब तो बताना पड़ेगा कि अंबानी का नाम भारत सरकार में किसके तरफ से आया था। ज़ुबानी आया था या दस्तावेज़ों में ये नाम जोड़ा गया था। और इस नाम के लिए किसने ज़ोर डाला था कि फ्रांस के राष्ट्रपति के पास दूसरा विकल्प नहीं बचा था। मोदी जी, आपकी तरफ से कौन था तो अंबानी कंपनी के अलावा सारे विकल्पों को ग़ायब कर रहा था और क्यों कर रहा था ?

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान एनडीटीवी की पेरिस स्थित पत्रकार ने भारत सरकार से उन उद्रपतियों की सूची मांगी थी जो एक ईवेंट में बोलने वाले थे। सरकार की तरफ से लिस्ट देने में आना-कानी की गई और जब मिली तो उस लिस्ट से गौतम अडानी का नाम ग़ायब था। अनिल अंबानी का नाम नीचली पंक्ति में था। नुपूर तिवारी को फ्रांस सरकार से जो लिस्ट मिली उसमें अनिल अंबानी और गौतम अडानी का नाम सबसे ऊपर की पंक्ति में था।

हे हिन्दी के पाठकों, क्या आपको इसी से संदेह नहीं होता कि फ्रांस सरकार की लिस्ट में गौतम अडानी और अनिल अंबानी के नाम सबसे ऊपर हैं। भारत सरकार की लिस्ट में अनिल अंबानी का नाम नीचे है ताकि किसी को उनकी मौजूदगी की प्रमुखता पर शक न हो। गौतम अडानी का नाम क्यों ग़ायब था।

अब आते हैं फ्रांस सरकार की बयान पर। ओलान्द के बयान के बाद प्रवक्ताओं की सरकार को काठ मार गया। सारे वीर प्रवक्ता चुप हो गए। रक्षा मंत्रालय से ट्वीट आता है कि हम इन ख़बरों की जांच कर रहे हैं। फ्रांस की सरकार के जवाब पर हिन्दी में ग़ौर करें क्योंकि ये सारी बातें आपके हिन्दी के अख़बार और चैनल ग़ायब कर देंगे। यह आपका दुर्भाग्य है कि आपको रफाएल का घोटाला ही नहीं समझना है, मीडिया का घोटाला भी बोनस में समझना है।

"फ्रांस सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है कि फ्रेंच कंपनी के साथ कौन सी भारतीय कंपनी साझीदार होगी। इन विमानों के ख़रीदने के भारत की जो तय प्रक्रिया है, उसके तहत फ्रांस की कंपनियों को अपना भारतीय साझीदार चुनने की पूरी आज़ादी है कि वे किसे ज़्यादा ज़रूरी समझती हैं। इसके बाद वे इसे भारत की सरकार के सामने मंजूरी के लिए रखती हैं, कि फ्रांस की कंपनी इस भारतीय कंपनी के साथ काम करना चाहती है।"

फ्रांस सरकार ने ओलान्द के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की। खंडन तक नहीं कहा। फ्रांस सरकार के इस बयान के अनुसार अंबानी के नाम की मंज़ूरी भारत सरकार ने दी है। फ्रांसुआं ओलान्द के अनुसार अंबानी का नाम भारत सरकार की तरफ से सुझाया गया था। क्या आपको अब भी कोई इसमें अंतर्विरोध दिखता है? क्या अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में यह बताई थी कि अंबानी की कंपनी को मंज़ूरी सरकार ने दी है? अब तो उन्हें एक और ब्लॉग लिखना ही होगा कि अंबानी का नाम भारत की तरफ़ से किसने दिया था ?

अनिल अंबानी की कंपनी जुम्मा जुम्मा चार दिन की थी। सरकारी कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (HAL) को 50 से अधिक विमान बनाने का अनुभव है। साठ साल पुरानी यह कंपनी डील के आख़िरी चरण में शामिल है, अचानक ग़ायब कर दी जाती है और अनिल अंबानी की कंपनी साझीदार बन जाती है। जबकि डील से दो दिन पहले भारत के विदेश सचिव HAL के शामिल होने की बात कहते हैं। उसके कुछ दिन पहले डास्सो एविएशन के चेयरमैन कहते हैं कि "हमने रफाएल के बारे में बात की है। हम HAL के चेयरमैन से इस बात पर सहमत हैं कि हम प्रोडक्शन की जम्मिेदारियां साझा करेंगे। मैं मानता हूं कि करार अंतिम चरण में है और जल्दी ही इस पर दस्तख़त हो जाएंगे।"

इसका मतलब यही हुआ कि अनिल अंबानी की कंपनी की एंट्री अंतिम चरण में होती है। अब यह बात जांच से ही सामने आएगी कि अनिल अंबानी की कंपनी के नाम की चर्चा किस कमेटी में, कब और क्यों हुई। वायु सेना में किसे और रक्षा मंत्रालय में किस किस को पता था कि HAL की जगह अंबानी की कंपनी को साझीदार होना है। आखिर किसने एक सरकारी कंपनी के हित से समझौता किया, कौन था जो दिवालिया हो चुकी कंपनी को डिफेंस डील में पार्टनर बनाना चाहता था? फ्रांस के अख़बार मीडियापार्ट के संवाददाताओं से बात की है। एक संवाददाता ने कहा है कि हम इस डील की जांच कर रहे थे। फ्रांसुआं ओलान्द 2017 तक राष्ट्रपति रहे और वे इस डील के डोज़ियर को ख़ुद मैनेज कर रहे थे। रिपोर्टर ने नुपूर को बताया है कि ओलान्द ने यह बात साफ़-साफ़ कही है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि अनिल अंबानी कौन, इसका इतिहास क्या है, अनुभव क्या है, अनिल अंबानी का नाम भारत सरकार की तरफ से प्रस्तावित किया गया। ये रिपोर्टर जानना चाहते थे कि किस स्तर पर भारत की सरकार ने दखल दिया और एक कंपनी को घुसाने की कोशिश की। हमने जिन रक्षा जानकारों से बात की, वे सभी इस बात से हैरान हैं कि डास्सो एविएशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंपनी किसी ऐसी कंपनी से करार क्यों करेगी जिसका कोई अनुभव नहीं है।

इस बहस को इस बात पर ले जाने की कोशिश होती रहती है कि रफाएल विमान कितना शानदार और ज़रूरी है। वो तो है ही। भारत के लिए ही नहीं दुनिया भर के लिए है। सवाल है कि कौन इस डील में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था। इस डील के लिए भारत की एक पुरानी कंपनी को हटा कर एक प्राइवेट कंपनी को किसके कहने पर पार्टनर बनाया गया। मोदी जी को ही बताना है कि उनका पार्टनर कौन कौन है ?

मोदी सरकार प्रवक्ताओं की सरकार है। उसे अब कुतर्कों को छोड़ सवालों के जवाब देना चाहिए। बेहतर है कि मोदी जी अपने गुलाम एंकरों को छोड़ जो रक्षा कवर करने वाले धुरंधर पत्रकारों के बीच आएं और सवालों के जवाब दें। बनारस में बच्चों से कह कर चले आए कि सवाल पूछा करो। क्या अब उन बच्चों को याद दिलाने के लिए लाना होगा कि मोदी जी सवाल पूछा गया है उसका जवाब दिया करो। सीन नदी से आने वाली हवा गंगा पुत्र से पूछ रही है कि अंबानी का नाम कहीं आपने तो नहीं सुझाया। वर्ना लोग तो पूछेंगे कि बहुत याराना लगता है।

शिशु मंदिर से हिंदू विश्वविद्यालय तक के सफ़र से निकले अहम नोट्स

रोशन पाण्डे

मेरी पढ़ाई कक्षा शिशु (नर्सरी) से लेकर 11वीं तक आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल विद्या मंदिर में हुई. इन 12 वर्षों में जो कुछ वहाँ हो रहा था वह मेरे लिए सामान्य था. जब हम लंबे समय तक किसी खास तरह के माहौल में पले बढ़े होते हैं तो उसकी कमियों को नही देख पाते. अपने चारों ओर एक ही तरह की बातें सुनकर उसको ही सच मान लेते हैं. मेरी भी यही गति रही।

आरएसएस के मुखपत्र, उसकी किताबों और उनके विचारकों द्वारा जो बातें सुनने को मिलती हैं वे बातें विद्या मंदिर की कक्षाओं में रोजाना बतायी जाती थीं. देखते ही देखते आप कब साम्प्रदायिक बन जाते हैं पता ही नही चलता. सबसे पहले आपको हिन्दू होने पर गर्व कराया जाएगा. फिर यह बताया जाएगा कि आप बाकी धर्मों से श्रेष्ठ हैं. उसके बाद यह तर्क होता है कि अतीत में हमने सारी तकनीकी विकसित कर ली थी लेकिन मुस्लिमों के आतंक ने हमें पीछे कर दिया. हिन्दू धर्म को बचाने के लिए ईसाई मिशनरियों के खिलाफ जंग की बात की जाती है. छात्रों को शिविर और शाखाओं में लाया जाता है जहाँ उनके दिमाग में नफरत और हिंसा भरी जाती है. ऐसी बातें जिनका इतिहास और वैज्ञानिकता से कोई नाता नहीं है, वे रोजाना की बातचीत का हिस्सा होती हैं. जैसे- देश में आज इतनी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि नेहरू ने रात 12 बजे आजादी को घोषणा कर दी, हस्तमैथुन से नपुंसकता आती है, आदमी तभी कामयाब हो सकता है जब वह स्त्री से उचित दूरी बनाए रखे, इत्यादि।

मुझे खुद नहीं पता कि यह सब सुनते-पढ़ते मैं कब गांधी, नेहरू और वामपंथियों का दुश्मन हो गया. वामपंथ शब्द से नफरत हो गयी थी क्योंकि मुझे बताया गया कि ये मानते हैं कि जिसके पास बंदूक है वो उसके दम पर सत्ता हांसिल कर सकता है. मैं खुद को मनु की संतान मानने लगा था. राष्ट्रीय प्रतीकों की राजनीति करने वाले संघ के स्कूल पर हमेशा भगवा ध्वज लहराता है. हमें यह बताया गया कि यही हमारा असली झंडा है. रोज सुबह प्रार्थना में गोलवलकर, सावरकर की बड़ी तस्वीर और उनके महिमामंडन से मुझे उनके करीब ला दिया. राम मंदिर मामले में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आना था तब हम लोगों से जबरन 108 बार हनुमान चालीसा पढ़वायी गयी।

बनारस हिंदू युनिवर्सिटी आने के बाद जब आधुनिक विचारों से मैं रूबरू हुआ और अलग-अलग स्कूलों से आए दोस्तों से बात की, तब जाकर आरएसएस के स्कूलों का एजेंडा समझ आया. यूनिवर्सिटी आने के बाद जब इनको मैंने पढ़ना शुरू किया तब समझ में आया कि किस खतरनाक एजेंडे के तहत हमारी पीढ़ियों को दंगाई बनाया जा रहा है. जातिवाद और पितृसत्ता का कूड़ा उनके दिमाग में ठूंसा जा रहा है. संवाद की कोई संस्कृति नहीं है यहां, शिक्षा डंडे के बल पर दी जाती है. एक शिक्षक जिसके द्वारा मेरा दो साल उत्पीड़न किया गया, मेरे सवाल करने पर वो डंडे बरसाने लगता।

तब मुझे लगता था ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है जिसकी बुनियाद डर पर टिकी है लेकिन बाद में समझ आया कि आरएसएस की राजनीति की बुनियाद ही डर है. पहली कक्षा से यह बात सुनते आया हूँ कि इंसान को भगवान, माँ-बाप और शिक्षक से जरूर डरना चाहिए. वहाँ डर एक संस्कार है जिसके नाम पर छात्रों के अंदर की क्रिएटिव और क्रिटिकल सोच का कत्ल कर दिया जाता है।

एक सोची समझी रणनीति के तहत 'हिंदुत्व' की राजनीति को इन शिशु मंदिरों के माध्यम से इस देश में उभारा गया. 1946 में गोलवरकर ने प्रथम आरएसएस स्कूल की स्थापना गीता स्कूल के नाम से की. महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया. जनता में इसका असली चेहरा सामने आ चुका था. आनन-फानन में सरस्वती शिशु मंदिर मॉडल लाया गया और 1952 में गोरखपुर से पहले शिशु मंदिर की शुरुआत हुई. 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विद्या भारती की स्थापना हुई और बड़े स्तर पर स्कूली शिक्षा में आरएसएस ने हस्तक्षेप शुरू किया. तमाम सामाजिक कार्यों के जरिए संघ लोगों से जुड़कर पहले जनसंघ और अब भाजपा के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश करता रहा है।

1997 में आरएसएस के सुरुचि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'परम वैभव के पथ पर' में संघ द्वारा बनाए गये 30 से ज्यादा संगठनों का जिक्र है जो हिंदुत्व के एजेंडे पर अलग-अलग पहचानों के साथ काम कर रहे हैं. इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी नाम शामिल है। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो सिद्ध करते हैं कि भारत में साम्प्रदायिक हिंसा और हिंदुत्व का एजेंडा फैलाने के लिए इसे भारी मात्रा में विदेशी सहयोग भी मिलता है. 11 जुलाई 2014 को फ्रंटलाइन में छपी अजय आशीर्वाद की रिपोर्ट 'होली काउ' के अनुसार 1994 से 2000 के बीच सिर्फ अमेरिका से पांच मिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग हुई है. यह फंडिंग इंडिया डेवलपमेंट एंड रिलीफ फण्ड (IDRF) के माध्यम से हुई थी. संघ व उसकी अनुषंगी संस्थाओं को विदेश में मिलने वाले अनुदान पर एक विस्तृत रिपोर्ट ''हिंदू नेशनलिज्म इन द युनाइटेड स्टेट्स'' के नाम से साउथ एशिया सिटिजंस वेब पोर्टल के माध्यम से सामने आई थी जिसे नीचे पूरा पढ़ा जा सकता है।

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर में विद्या भारती द्वारा 40 हजार स्कूल संचालित किए जा रहे हैं जिसमें 40 लाख से ज्यादा छात्र दाखिल हैं. इन स्कूलों में लाखों शिक्षक हैं जो रोज सुबह शाखाओं में जाते हैं. ये शिक्षक अपने परिवार के मुखिया भी हैं. स्कूली शिक्षा का उद्देश्य होता है तर्कशील नागरिक तैयार करना जो अपने अधिकारों और समाज को लेकर संवेदनशील हो. स्वतंत्र दिमाग का व्यक्ति ही अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकता है और लोकतान्त्रिक समाज की स्थापना कर सकता है, लेकिन आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल छात्र के दिमाग को संकीर्ण बना देते हैं और उसके व्यक्तित्व विकास की संभावनाओं को रोक देते हैं।

इस तरह के संगठन भारतीय लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हैं. ये सच है कि सबको अपनी विचारधारा प्रैक्टिस करने का अधिकार है लेकिन क्या समाज को हिंसा की आग में धकेलने वालों को इसकी छूट दी जा सकती है? हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से निकले मूल्य आज खतरे में हैं. धर्मनिरपेक्षता समाज में गाली बनती जा रही है. नब्बे साल समाज में नफरत फैलाने वाले आज सत्ता में हैं. पाठ्यक्रम तेजी से बदले जा रहे. किताबें हमें और ज्यादा साम्प्रदायिक बनाने का जरिया बनती जा रही. हम जो नागरिक समाज बनने की प्रक्रिया में थे अब दंगाई होते जा रहे हैं।

लोकसभा चैनल का जनपक्ष बनाम सरकारी पक्ष

दीपिका झा

क्या आप, न्यूज चैनल पर जो कुछ भी दिखाया जाता है उसे सच मानकर बैठ जाते हैं? उम्मीद है कि पोस्ट ट्रूथ के इस जमाने में आपको मीडिया की इस सच्चाई से रूबरू करवाने की जरूरत नहीं है। पर फ़िर भी यह कह दें कि अगर आपको दिमागी दिवालियापन से बचना है तो भोंपू चैनलों को देखना बंद कर दें।

किसी भी सरकार की सफ़लता का पता वहां की मीडिया की स्वतंत्रता से चलता है पर भारतीय मीडिया कितनी स्वतंत्र है वह मुझे मीडिया स्टुडेंट के तौर पर एक चैनल विजिट करते समय महसूस हुआ। सभी छात्र बतौर दर्शक और भागीदार बनकर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गये। स्वछता अभियान को लेकर बना यह कार्यक्रम विशुद्ध रूप से सरकारी प्रचार से अधिक कुछ नहीं था। क्योंकि लोकसभा चुनाव में मात्र 6 महीने बचे हैं।

स्वछता आंदोलन कार्यक्रम में बात हुई तो केवल स्वछता को लेकर स्वाभाविक परिवर्तन में बदलाव की एक-एक करके सबने चैनल द्वारा रटाये गये सवालों के जवाब दिये। जैसे अब हम रैपर बैग में रखते हैं और अब हम आस पड़ोस में भी सफ़ाई रखते हैं। पर असल मुद्दे की बात जो सवाल सबसे गंभीर था कि आखिर मैनहॉल में जाकर सफ़ाईकर्मी का क्या, जिनकी मौत सीवर में बिना किसी उपकरण के जाने की वजह से हो रही है। जिस पर कोई ठोस ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है।

जब आप बुलेट ट्रेन ला सकते हैं तो फ़िर सीवर साफ़ करने के लिये मशीन का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? एक पैनेलिस्ट ने जब स्वछता कर्मचारी के मुद्दे पर सवाल उठाए तो एंकर जल्दी से दूसरे पैनेलिस्ट की तरफ़ पहुंच गया और बाद में बड़ी चालाकी से समय का हवाला देते हुये कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। सबसे दुखद तो यह था कि स्वछता के लिये या यूं कहें कि मैनहॉल में जाकर सफ़ाई करते वक्त जान गंवा देने वाले एक कर्मचारी के पिता और भाई वहां मौजूद थे। जब उस मृतक कर्मचारी के भाई ने कहा कि उसके भाई से जबरदस्ती इस तरह का काम करवाया गया है तो यह कहकर टाल दिया गया कि हम इस बात पर वापस आते हैं। फ़िर कार्यक्रम ही समाप्त। पूरे कार्यक्रम में मृत कर्मचारी के पिता और भाई को अपनी बात रखने को मौका नहीं दिया गया।

असल में स्वछता आन्दोलन कितना सफ़ल है और विज्ञापन के अलावा सफ़ाई मशीनों पर कितना खर्च किया गया है। यह सवाल उठ ही नहीं पाया। सच्चाई को बड़ी होशियारी के साथ दबा दिया गया। असल बात तो यह है कि आप अभी एक के बाद एक भाजपा सरकार की योजनाओं की 'सफ़लता' के गुणगान वाले कार्यक्रम टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे क्योंकि चुनाव सर पर है। इसलिये यह प्रचार भी काफ़ी जरूरी है। पर कृपया करके इन चैनलों और पैनेलिस्टों की बातों में न आकर दिमाग पर थोड़ा जोर डालें और सोचें क्या तमाम टीवी चैनल अगर कुछेक अखबारों को छोड़ दें तो क्या आपको सच दिखाते हैं? निसंदेह नहीं तो फ़िर मौजूदा सरकार के इस छलावे में न आयें कि इनकी योजनाओं में अपार सफ़लता हासिल की है और देश तरक्की की ओर जा रहा है।